

## भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

## (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, गया Project Implementation Unit-Gaya

हाउस न 70/244, जुडिशियल क्वार्टर के सामने चाणक्यापुरी कॉलनी, गया (बिहार) CUG NO. 8130006225 H.No. 70/244, Opp. Judicial Quarter Chanakyapuri Colony, Gaya - 823 001 (Bihar)

दूरभाष/Tele : 0631-2222337 ई-मेल/E-mail: gaya@nhai.org, piugayanh83@gmail.com वेबसाइट/Website www.nhai.org

NHAI/PIU-GAYA/NH-119D/PKG-2/FC/662

Date - 24.07.2024

To,
Additional Principal Chief Conservator of Forest (CAMPA) –
cum – Nodal Officer (Forest Conservation),
Bihar, Patna

Sub – Construction of Four Lane Access Controlled Greenfield National Highway from Shivrampur (Ch. 55+0002) to Ramnagar (Ch. 109+324) of NH – 119D under Bharatmala Pariyojana in the State of Bihar (Amas – Darbhanga Package – II of 54.322 km) – Stage II Forest Clearance for 3.142 Ha Forest land in Jehanabad Dist. – reg.

Ref – APCCF (CAMPA) – cum – Nodal Officer (Forest Conservation)

Sir,

In reference to the subject matter, it is submitted that the construction works of Project "Construction of Four Lane Access Controlled Greenfield National Highway from Shivrampur (Ch. 55+0002) to Ramnagar (Ch. 109+324) of NH – 119D under Bharatmala Pariyojana in the State of Bihar (Amas – Darbhanga Package – II of 54.322 km)" is ongoing under Hybrid Annuity Mode (HAM), whereby, Strip Plantation on both sides of the road as per IRC norms is included in the scope of works of Concessionaire & the corresponding costs is included under HAM Agreement. Therefore, plantation shall be done by our Concessionaire on the project stretch.

Thanking you.

Yours faithfully,

(Gulam Qadir)
Project Director

Copy to -,

1. RO – Patna, NHAI – for kind information, please.

2. CF, Gaya Division, Gaya – for kind information, please.

3. DFO, Gaya – for kind information, please.

Head Office : G-5&6, Sector - 10, Dwarka, New Delhi - 110075, जी-5 एवं 6, सेक्टर - 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 दूरभाष/Phone : 91-11-25074100/25074200, फैक्स/Fax : 91-11-25093507/25093514, Website : www.nhai.org



#### बिहार सरकार

## पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना। (कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना—800 014 संख्या—व.सं. / 06 / 2022 — प्राप्

प्रेषक.

अरविन्दर सिंह भा०व०से० अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) –सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना।

सेवा में,

परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, गया।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया।

पटना 14, दिनांक- 23/07/2024

विषय – भारतमाला परियोजना के तहत जहानाबाद जिलान्तर्गत शिवरामपुर-रामनगर (55.002–109.324 कि॰मी॰) पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3.142 हे॰ वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर पृच्छा के संबंध में।

प्रसंग – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय राँची का पत्रांक FP/BR/Road/143461/2021/368 दिनांक 22.06.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारतमाला परियोजना के तहत जहानाबाद जिलान्तर्गत शिवरामपुर—रामनगर (55.002—109.324 कि॰मी॰) पथ निर्माण कार्य से संबंधित प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा पृच्छा की गयी है जो प्रसंगाधीन पत्र (छायाप्रति संलग्न) में स्वतः स्पष्ट है।

अतः आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा की गयी पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0—यथोक्त।

विश्वासभाजन, ह0 / — (अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) –सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- व.सं / 06 / 2022- ५७५ दिनांक- 23 / ०५/२० ८ ५ प्रतिलिपि - वन संरक्षक, गया अंचल, गया को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) —सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना।



## भारत सरकार / Government of India पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

### Ministry of Environment, Forest & Climate Change क्षेत्रीय कार्यालय/ Regional Office

पताः द्वितीय तल्, झारखण्ड राज्य आवास वोर्ड मुख्यालय, हरमू चोक, राँची, झारखण्ड - 834002 Add: 2<sup>nd</sup> Floor, Headquarter-Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchl, Jharkhand - 834002

Tel: 0651-2410002, 2410007; E-mail: ro.ranchi-mef@gov.in

File No. FP/BR/ROAD/143461/2021/368 सेवा में,

> प्रधान सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, सिंचाई भवन, पटना - 800015.



विषय: भारतमाला परियोजना के तहत जहानाबाद जिलान्तर्गत शिवरामपुर-रामनगर (55.002-109.324 कि.मी.) पथांश निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3.142 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में |

महाशय,

उपरोक्त विषय में इस कार्यालय को प्राप्त श्रीमान के पत्र संख्या वन भूमि-37/2022-244(ई.)/प॰व॰ज॰प॰, पटना-15, दिनांक 04.06.2024 के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि विषय वर्णित परियोजना हेतु वन-भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की आपके द्वारा प्रेषित सैद्धांतिक स्वीकृती के शतों की अनुपालना आख्या के जाचीपरांत उसमें कतिपय किमयाँ पायीं गई हैं। अतः यह अवगत करते हुए कि सेद्धांतिक स्वीकृती जारी होने के पश्चात क्या परियोजना सम्बन्धी कार्य करने की स्वीकृति सक्षम स्तर से जारी की गयी है व क्या कार्य पूर्ण/प्रगतिरत है, अनुपालना को पुनः प्रसंस्कृत कर निम्नलिखित दस्तावेजो/जानकारी को अपलोड कराने की कृपा करे;

The condition no. B(5) of in-principle approval prescribes, "The State Forest Department

should raise Strip Plantation on both sides of the road as per the IRC norms" .

To which the State Government has submitted in the compliance letter, "प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शतों के अनुपालन से संबंधित वचनबद्धता समर्पित की गयी है जो इस पत्र के साथ संलग्न है |" whereas, user agency has submitted, "Pertains to State Forest Department", in its undertaking.

Therefore, compliance in respect of condition no. B(5) of Stage-I approval as furnished by State Govt. and the User Agency are not in consonance to each other. Thus, state government is required to clearly state that the strip plantation shall be raised by state forest department on project cost and user agency is required to submit consenting undertaking.

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित दस्तावेजो/जानकारी को प्रस्ताव पर अग्रेतर करवाई हेतु ऑनलाइन में अपलोड

कराते हए प्रेषित कर अनुगृहित किया जाये | विश्वासभाजन

Signed by Shashi Shankar Pathak Date: 22-06-2024 11:56:14 (शशि शंकर )

उप वन महानिरीक्षक

प्रतिलिपि:-

- 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक- सह नोडल पदाधिकारी (एफ. सी.), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, विहार सरकार, अरण्य भवन, श्रहीद पीर अली लां मार्ग, पटना-
- 2. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गया वन प्रमण्डल, गया, विहार।
- 3. परियोजना निदेशक, NHAI, PIU, गया, विहार 823001.
- 4. गार्ड फाईल I

1



# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)

## National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, गया Project Implementation Unit-Gaya

हाउस नं 70/244, जुडिशियल क्वार्टर के सामने चाणक्यापुरी कॉलनी, गया (बिहार) H.No. 70/244, Opp. Judicial Quarter Chanakyapuri Colony, Gaya - 823 001 (Bihar)

दूरभाष/Tele : 0631-2222337 ई−मेल/E-mail: gaya@nhai.org, piugayanh83@gmail.com वेबसाइट/Website : www.nhai.org
11013/NHA//PILLGaya/2023/ िं ७

11013/NHAI/PIU-Gaya/2023/ 5 8 2



To,

The Divisional Forest Officer

Gaya Forest Division Gaya, Bihar

Sub: In-principal approval (Stage-I) approval of Development of 4 lane inter corridor (Green field alignment) from Shivrampur (Old NH-2/New NH-19) to Ramnagar under Bharatmala Pariyojna (Lot-5/Package-7) in State of Bihar- Package-II from Shivrampur (Ch.55+002) to Ramnagar (Ch. 109+327))- Total Length 54.325 Km. (Online Proposal No. FP/BR/ROAD/143461/2021): Submission of Compliance report for obtaining Final (Stage-II) Forest Clearance- Reg.

Ref: (1) M/s SA Infra letter No-SAICPL/Bharatmala/DPR/Lot-5/Pkg-7/2023/21362 dt.05.06.2023

(2) MoEF&CC, IRO- Ranchi, GOI letter No: FP/BR/Road/143461/2021/723 dt.28.11.2022 Sir,

Please refer to the letter u/r (2) vide which MoEF&CC, IRO- Ranchi has accorded In-principal approval for diversion of 3.142 ha forest land for "Development of 4 lane inter corridor (Green field alignment) from Shivrampur (Old NH-2/New NH-19) to Ramnagar under Bharatmala Pariyojna (Lot-5/Package-7) in State of Bihar."

In this regard, point-wise compliances of In-principal approval (Stage-I FC) granted by Govt. of India, MoEFCC, IRO, Ranchi is submitted below:

## A. Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department:-

SI.	Conditions of In-principal approval	Compliances made by the User
No.	34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Agency i.e. NHAI
(1)	The Cost of compensatory afforestation on the CA land (6.5 ha) at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	Cost of compensatory afforestation (CA) amounting to Rs.25,81,777/ - & Net Present Value (NPV) amounting to Rs.30,09,345/ - (Total amount of CA & NPV Rs.55,91,122/-) as per demand received from State Forest Department vide letter no. \(\bar{a}\)/\(\sigma\)/\(\sigm
(2)	The state Govt. shall charge the Net Present	Annexure-I. The payment made by User
	Value (NPV) for the 3.142 ha forest area to be	Agency, is also renecting with
	diverted under this proposal from the User	101

Head Office : G-5&6, Sector - 10, Dwarka, New Delhi - 110075, जी-5 एवं है, सिक्टर - 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 जाउ दूरभाष/Phone : 91-11-25074100/25074200, फैक्स/Fax : 91-11-25093507/25093514, Website : www.nhai.org

	Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and 5-3/2011-FC(Vol-I) dated 19/01/2022 in this regard.	transaction ID 839563 in Part-II on the Parivesh Portal.
(3)	All the funds received from the user Agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	
(4)	The KML files of the area to be diverted and the CA area shall be uploaded on the e-green watch portal with all requisite details and submitting compliance report for seeking stage-II approval.	Pertains to Forest Department.
(5)	The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	FRA 2006 certificate has been issued by the District Collector, Jehanabad vide letters no. 1130, 1131, 1132 & 1133 dated 02.06.2023, copies of FRA Certificates are enclosed as Annexure-II.
(6)	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	Agreed
(7)	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	Compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).

(B) Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the user agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:

SI. No.	Conditions of In-principal approval	Compliances made by the User Agency i.e. NHAI	
1.	Legal status of the forest land will remain unchanged;	Agreed	
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 6.5ha. degraded forest land (Site –Baikh, Range – Jehanabad,	d	

(2/4)

	0 1 1 00 1 0 5 1 0 1	
	Compartment No.38 under Gaya Forest Division)	
	at the cost of the user agency. As far as possible,	
	a mixture of local native species shall be planted	
	and monoculture of any species, especially non-	
	native species should be avoided.	
3.	Additional amount of the NPV of the diverted	
	forest land, if any, becoming due after finalization	
	of the same by the Hon'ble Supreme Court of	Agreed
	India on receipt of the report from the Expert	
	Committee, shall also be charged by the State	
	Government from the User Agency. The User	2
	Agency shall furnish an undertaking to this effect.	
4.	User Agency shall restrict the felling of trees to	
٦.	minimum number in the diverted forest land and	Agreed
	the trees shall be felled under the strict	Agreed
	supervision and permission of the State Forest	
	Department and the cost of felling of trees shall	ė.
	be deposited by the User Agency with the State	
	Forest Department. Further, in view of the State	
	Government's recommendation, such number of	
	trees whose removal is unavoidable, and whose	· ·
	translocation (species, number and girth to be	
	decided by SFD) is practicable, will be	
	translocated to the extent possible at the cost of	
	user agency.	
5.	The State Forest Department shall raise Strip	1
	Plantation on both sides of the road as per the	Pertains to State Forest Department.
	IRC norms on the basis of available blank area in	
	ROW by using plastic wire mesh at cost provided	
	by the User Agency.	
6.	(a) The User Agency shall ensure that the	
	labourers and staff engaged in construction	*
	activities do not damage the nearby forest flora	
	and fauna.	Agreed
	(b) The User Agency shall provide alternate fuels	v.
	preferably LPG to the labourers and staff working	
	at the site so as to avoid any damage and	4
	pressure on the nearby forest areas.	
7.	The layout plan of the proposal shall not be	
	changed without prior approval of the Ministry of	Agreed
	Environment, Forest & Climate Change.	

8.	(a) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	
	(b) The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life/ requirement.	Agreed
	(c) The Forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.	
9.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	

Note: Undertaking w.r.t. conditions mentioned at para B. (1 to 9) is also enclosed.

In view of above, it is requested to process the proposal for grant of final (Stage-II) Forest Clearance under FCA, 1980 at the earliest for the above mentioned project.

Encl:- As above

Yours faithfully

(Gulam Qadir), Project Director

Copy to: (1) The APCCF-cum-Nodal Officer (FC), O/o PCCF, Aranya Bhawan, Shaheed Peer Ali Khand Marg, Post-Veterinary College, Patna 800 014, Bihar, for information please.

(2) M/s SA Infra, for necessary action.

(4/4)



## भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)

## **National Highways Authority of India**

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India) परियोजना कार्यान्वयन इकाई, गया Project Implementation Unit-Gaya

हाउस नं 70/244, जुडिशियल क्वार्टर के सामने चाणक्यापुरी कॉलनी, गया (बिहार) H.No. 70/244, Opp. Judicial Quarter Chanakyapuri Colony, Gaya - 823 001 (Bihar)

दूरभाष/Tele : 0631-2222337 ई-मेल/E-mail: gaya@nhai.org, piugayanh83@gmail.com वेबसाइट/Website : www.nhai.org



#### Undertaking

Sub.: In-principal approval (Stage-I) approval of Development of 4 lane inter corridor (Green field alignment) from Shivrampur (Old NH-2/New NH-19) to Ramnagar under BharatmalaPariyojna (Lot- 5/Package-7) in state of Bihar- Package-II from Shivrampur (Ch.55+002) to Ramnagar (Ch. 109+327))-Total Length 54.325 km. (Online Proposal No. FP/BR/ROAD/143461/2021): Undertakings for obtaining Final (Stage-II) Forest Clearance-Reg.

Ref: MoEF&CC, IRO- Ranchi, GOI letter No: FP/BR/Road/143461/2021/723, dated 28.11.2022

The user agency NHAI, PIU Gaya hereby undertakes the following:

- 1. That the Legal status of the forest land will remain unchanged.
- That the User Agency i.e., NHAI shall deposit Additional amount of the NPV of the diverted forest land,
  if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of
  the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User
  Agency.
- 3. User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision and permission of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department. Further, in view of the State Government's recommendation, such number of trees whose removal is unavoidable, and whose translocation (species, number and girth to be decided by SFD) is practicable, will be translocated to the extent possible at the cost of user agency.
- 4. (a) The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged in construction activities do not damage the nearby forest flora and fauna.
  - (b) The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.
- 5. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.
- (a) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
  - (b) The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life/requirement.
    - (c) The Forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.
- 7. That NHAI further undertakes to abide any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.

Project Director NHAI, Pro Gaya

## **Transfer Money**



#### CONFIRMATION

Transfer Money submitted successfully.



e-Receipt

Reference Number

Status

0401CBA72DDD

Completed

Account to be debited

Account to be credited

1967201001013

BIHAR CAM2

**Account Number** 

IFSC Code

1506261143461893

UBIN0996335

Account Type

Amount ₹

Domestic - Savings

₹ 55,91,122.00

Transaction Date

Pay Via

04 Jan 2023

**NEFT** 

What would you like to do next?









More Payment Options

Go To Dashboard

Add Favourite

Set Repeat Transfer



Print

## कार्यालय, जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु FRA 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.01.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या- 1130 दिनांक 02/06/2023

वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल गया का पत्र संख्या—26, दिनांक—02.01.2023 जहानाबाद जिलान्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या—119D भारतमाला परियोजना अन्तर्गत शिवरामपुर (Ch.55+002) से रामनगर (Ch.109+337) में मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु अंचल मखदुमपुर मौजा डकरा, खेसरा संख्या—153, 154, 106 वन संरक्षण अधिनियम—1980 के अन्तर्गत 0.45 हेक्टेयर वन भूमि का अपयोजन (Diversion) के क्रम में अनुशंसा किया गया है।

अंचल अधिकारी, मखदुमपुर का पत्र संख्या—1090, दिनांक—27.05.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उपरोक्त वर्णित परियोजना क्षेत्र में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या—119D भारतमाला परियोजना अन्तर्गत शिवरामपुर (Ch.55+002) से रामनगर (Ch.109+337) में मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु अंचल मखदुमपुर मौजा—डकरा, खेसरा संख्या—153, 154, 106 वन संरक्षण अधिनियम—1980 के अन्तर्गत 0.45 हेक्टेयर वन भूमि का वर्ष 2001 एवं 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति नहीं है।

प्राप्त अनुशंसा एवं जॉच प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कण्डिका—1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपन दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधी में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गॉव में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थानः— जहानाबाद तिथिः— 3//05/2013

जिला पदाधिकारी जहानाबाद।

#### OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13<sup>th</sup> day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and Census-2011

Place: Jehanabad Date: 31)5/2023

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेत् FRA 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.01.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या- 1/32 दिनांक 62/66/2023

वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल गया का पत्र संख्या-26, दिनांक-02.01.2023 जहानाबाद जिलान्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-119D भारतमाला परियोजना अन्तर्गत शिवरामपुर (Ch.55+002) से रामनगर (Ch.109+337) में मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु अंचल काको मौजा महम्मदपुर, खेसरा संख्या—121,122,123,99 वन संरक्षण अधिनियम—1980 के अन्तर्गत 1.008 हेक्टेयर वन भूमि का अपयोजन (Diversion) के क्रम में अनुशंसा किया गया है।

अंचल अधिकारी, काको का पत्र संख्या-796, दिनांक-26.05.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उपरोक्त वर्णित परियोजना क्षेत्र में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–119D भारतमाला परियोजना अन्तर्गत शिवरामपुर (Ch.55+002) से रामनगर (Ch.109+337) में मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु अंचल काको, मौजा-महम्मदपुर, खेसरा संख्या-121,122,123,99 वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत 1.008 हेक्टेयर वन भूमि का वर्ष 2001 एवं 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति नहीं है।

प्राप्त अनुशंसा एवं जॉच प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कण्डिका-1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपन दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधी में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गाँव में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थान:- जहानाबाद तिथि:- 31/05/2023

जिला पदाधिकारी जहानाबाद।

#### OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and Census-2011

Place: Jehanabad Date: 31/05/2023

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेत् FRA 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.01.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या- 1/33 दिनांक 02/06/2023

वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल गया का पत्र संख्या—26, दिनांक—02.01.2023 जहानाबाद जिलान्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या—119D भारतमाला परियोजना अन्तर्गत शिवरामपुर (Ch.55+002) से रामनगर (Ch.109+337) में मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु अंचल मोदनगंज, मौजा गंधार, खेसरा संख्या—2927,2928,2929,2921,2922,2930 के अन्तर्गत 0.924 हेक्टेयर एवं मौजा विश्ननपुर ओकरी, खेसरा संख्या—456, वन संरक्षण अधिनियम—1980 के अन्तर्गत 0.490 हेक्टेयर, कुल—1.414 हेक्टेयर, वन भूमि का अपयोजन (Diversion) के क्रम में अनुशंसा किया गया है।

अंचल अधिकारी, मोदनगंज का पत्र संख्या-937, दिनांक-26.05.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उपरोक्त वर्णित परियोजना क्षेत्र में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–119D भारतमाला परियोजना अन्तर्गत शिवरामपुर (Ch.55+002) से रामनगर (Ch.109+337) में मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु अंचल मोदनगंज, मौजा गंधार, खेसरा संख्या—2927,2928,2929,2921,2922,2930 के अन्तर्गत 0.924 हेक्टेयर एवं मौजा विशुनपुर ओकरी, खेसरा संख्या–456, वन संरक्षण अधिनियम—1980 के अन्तर्गत 0.490 हेक्टेयर, कुल—1.414 हेक्टेयर, वन भूमि का वर्ष 2001 एवं 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति नहीं है।

प्राप्त अनुशंसा एवं जॉच प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कण्डिका-1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपन दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधी में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गाँव में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति

की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थानः– जहानाबाद तिथिः– ...3//05/2023

जिला पदाधिकारी जहानाबाद।

OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and Census-2011

Place:- Jehanabad Date: 2105/20

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु FRA 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.01.2014 न एवं जलवायु नार्याः को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या- 1213 दिनांक

वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल गया का पत्र संख्या-2492, दिनांक-09.06.2023 जहानाबाद जिलान्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-119D भारतमाला परियोजना अन्तर्गत शिवरामपुर (Ch.55+002) से रामनगर (Ch.109+337) में मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु अंचल घोषी, मौजा गोलकपुर, खेसरा संख्या-732,716,568,569,670,715 वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत 0.270 हेक्टेयर वन भूमि का अपयोजन (Diversion) के क्रम में अनुशंसा किया गया है।

अंचल अधिकारी, घोषी का पत्र संख्या-1011, दिनांक-27.05.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उपरोक्त वर्णित परियोजना क्षेत्र में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-119D भारतमाला परियोजना अन्तर्गत शिवरामपुर (Ch.55+002) से रामनगर (Ch.109+337) में मजबूतीकरण एवं चौडीकरण कार्य हेतु अंचल घोषी, मौजा-गोलकपुर, खेसरा संख्या-732,716,568,569,670,715 वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत 0.270 हेक्टेयर वन भूमि का वर्ष 2001 एवं 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति नहीं है।

प्राप्त अनुशंसा एवं जॉच प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कण्डिका-1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपन दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधी में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गाँव में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थान:- जहानाबाद तिथि:- /३/06/23 प्रभारी पदाधिकारी

GISTOTOLG

जिला पदाधिकारी जहानाबाद।

### OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and Census-2011

Place:- Jehanabad Date: (3/6/23.....

ea olo ea

## बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना। (कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना—800 014 संख्या—व.सं. / 06 / 2022 103 /2

प्रेषक,

नन्द कुमार मांझी उप वन संरक्षक।

सेवा में.

परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, गया।

पटना 14, दिनांक-05/12/2022

विषय – भारतमाला परियोजना के तहत जहानाबाद जिलान्तर्गत शिवरामपुर-रामनगर (55.002–109. 324 किं०मी०) पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3.142 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/ROAD/143461/2021/723 दिनांक 28.11.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार ने विषयाधीन परियोजना के निर्माण हेतु 3.142 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर दो भाग (भाग—A एवं B) में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग—A में 1—7 शर्तें तथा भाग—B में 1—9 शर्तें अधिरोपित है जिसका कंडिकावार अनुपालन आपके स्तर से अपेक्षित है।

2. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग—A के शर्त संख्या 1 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं वर्त्तमान मजदूरी पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू० 25,81,777/— (रूपये पच्चीस लाख इकासी हजार सात सौ सत्तहर) मात्र का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

उक्त राशि का आकलन वर्त्तमान मजदूरी दर रू० 373 / प्रतिमानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय—समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनीकरण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

- 3. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग—A के शर्त संख्या 2 के आलोक में परियोजना निर्माण के क्रम में 3.142 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि का NPV की राशि 9.57780 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रू० 30,09,345/— (रूपये तीस लाख नौ हजार तीस सौ पैतालीस) मात्र NPV के मद में प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।
- 4. उपर्युक्त CA एवं NPV मद की कुल राशि रू० 55,91,122/— (रूपये पचपन लाख इकानवें हजार एक सौ बाईस) मात्र को मंत्रालय के वेब—साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराई जाय।
- 5. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को UTR No एवं दिनांक के साथ e-challan की मूल प्रति दी जाय।

6. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र के भाग—A में सिन्निहित 1—7 शर्तों तथा भाग—B में सिन्निहित 1—9 शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।
अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(नन्द कुमार मांझी) उप वन संरक्षक।



#### भारत सरकार / Government of India पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय Ministry of Environment, Forest & Climate Change एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय/Integrated Regional Office

पताः द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय, हरमू चौक, राँची, झारखण्ड - 834002 Add: 2<sup>nd</sup> Floor, Headquarter-Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand - 834002 Tel: 0651-2410002, 2410007; E-mail: ro.ranchi-mef@gov.in



No.FP/BR/ROAD/143461/2021/ 723

Date: 28th November, 2022

सेवा में,

Sir,

प्रधान सचिव

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार, सिंचाई भवन पटना - 800015.



विषय: In-principle (Stage-I) approval of Central Government under Forest (Conservation) Act 1980 for diversion of 3.142 ha forest land in favour of National Highway Authority of India (NHAI) for construction of four lane Inter Corridor Package-II from Sivrampur (Km 55.00) to Ramnagar (Km 109.324), NH-119D under Bharatmala Pariyojna in Gaya district of Bihar - reg.

I am directed to refer to the State Govt.'s letter No.Van Bhumi-37/2022-552(E)/Pa.Va.Ja.Pa. dated 12.07.2022 and letter No.Va.Sa./06/2022-904 dated 19.10.2022 of the APCCF-cum-Nodal Officer (FC), Bihar on the above mentioned subject seeking prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change under section 2 of Forest (Conservation) Act, 1980.

After due consideration of the proposal of the State Government, the Central Government, hereby conveyed "in-principle" approval for diversion of 3.142 ha forest land in favour of National Highway Authority of India (NHAI) for construction of four lane Inter Corridor Package-II from Sivrampur (Km 55.00) to Ramnagar (Km 109.324), NH-119D under Bharatmala Pariyojna in Gaya district of Bihar, subject to the following conditions and stipulations.

A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.

The cost of compensatory afforestation on the CA land (6.5 ha) at the (1) prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate

provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.

- ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and letter No.5-3/2011-FC(Vol-I) dated 6/1/2022 in this regard.
- (3) All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).
- (4) The KML files of the area to be diverted and the CA area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details and submitting compliance report for seeking Stage-II approval.
- (5) The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
- (6) Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.
- (7) The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).

B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:

- (1) Legal status of the forest land shall remain unchanged.
- (2) Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 6.5 ha. degraded forest land (Site -Bhaikh, Range Jahanabad, Compartment No.38 under Gaya Forest Division) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species should be avoided.

- (3) Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
- (4) User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision and permission of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department. Further, in view of the State Government's recommendation, such number of trees whose removal is unavoidable, and whose translocation (species, number and girth to be decided by SFD) is practicable, will be translocated to the extent possible at the cost of user agency.
- (5) The State Forest Department should raise Strip Plantation on both sides of the road as per the IRC norms.
- (6) (a) The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged in construction activities do not damage the nearby forest flora and fauna.
  - (b) The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.
- (7) The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.
- (8) (a) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
  - (b) The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life/ requirement.
  - (c) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.
- (9) Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.

After receipt of the report from the State Government regarding due compliance and fulfillment of the above conditions and stipulations, formal approval will be issued in this regard under Section 2 of Forest (Conservation) Act, 1980. Transfer of forest land by the State Government to the user agency should not be given effect to till formal order approving diversion of forest land is issued by the

Ministry of Environment, Forest and Climate Change. To facilitate speedy execution of this project, the in-principle approval may be considered for issuance of working permission for commencement of works by the competent authority, if the required funds for NPV and all other compensatory levies specified in the in-principle approval are realized from the user agency and accordingly the State Government, by passing an order, may allow the commencement of work of the linear project in forest land for a period of one year (The detail guideline issued vide Ministry letter No. 11-306/2014-FC, dated 28.08.2015 may be referred).

विश्वासभाजन

(शशि शंकर) सहायक वन महानिरीक्षक

प्रतिलिपि:-

1. आई॰जी॰एफ॰, आर॰ओ॰एच॰क्यू॰, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003.

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff)/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक- सह – नोडल पदाधिकारी (एफ. सी.), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खां मार्ग, पटना-800014.

3. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गया वन प्रमण्डल, गया, बिहार।

4. परियोजना निदेशक, NHAI, PIU, गया, बिहार – 823001.

5. गार्ड फाईल।

सहायक वन महानिरीक्षक



#### **NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds**

Date: 19-12-2022

Agency Name.	NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA, PROJECT IMPLEMENTATION UNIT - GAYA
Application No.	61143461893
MoEF/SG File No.	FP/BR/ROAD/143461/2021
Location.	BIHAR
Address.	House No. 70/244, Chanakayapuri Colony, GayaGaya
Amount(in Rs)	5591122/-

**Amount in Words** :Fifty-Five Lakh Ninety-One Thousand One Hundred and Twenty-Two Rupees Only

## NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506261143461893 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

 This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

#### BANK COPY



#### **NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds**

Date: 19-12-2022

Agency Name.	NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA, PROJECT IMPLEMENTATION UNIT - GAYA
Application No.	61143461893
MoEF/SG File No.	FP/BR/ROAD/143461/2021
Location.	BIHAR
Address:	House No. 70/244, Chanakayapuri Colony, Gaya Gaya
Amount(in Rs)	5591122/-

**Amount in Words**: Fifty-Five Lakh Ninety-One Thousand One Hundred and Twenty-Two Rupees Only

## NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506261143461893 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

 This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

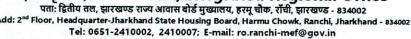
Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank



#### भारत सरकार / Government of India पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

### Ministry of Environment, Forest & Climate Change

## एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय/Integrated Regional Office





No.FP/BR/ROAD/143461/2021/ ヲ23

Date: 28th November, 2022

सेवा में,

#### प्रधान सचिव

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार, सिंचाई भवन पटना – 800015.

विषय: In-principle (Stage-I) approval of Central Government under Forest (Conservation) Act 1980 for diversion of 3.142 ha forest land in favour of National Highway Authority of India (NHAI) for construction of four lane Inter Corridor Package-II from Sivrampur (Km 55.00) to Ramnagar (Km 109.324), NH-119D under Bharatmala Pariyojna in Gaya district of Bihar – reg.

Sir,

I am directed to refer to the State Govt.'s letter No.Van Bhumi-37/2022-552(E)/Pa.Va.Ja.Pa. dated 12.07.2022 and letter No.Va.Sa./06/2022-904 dated 19.10.2022 of the APCCF-cum-Nodal Officer (FC), Bihar on the above mentioned subject seeking prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change under section 2 of Forest (Conservation) Act, 1980.

After due consideration of the proposal of the State Government, the Central Government, hereby conveyed "in-principle" approval for diversion of 3.142 ha forest land in favour of National Highway Authority of India (NHAI) for construction of four lane Inter Corridor Package-II from Sivrampur (Km 55.00) to Ramnagar (Km 109.324), NH-119D under Bharatmala Pariyojna in Gaya district of Bihar, subject to the following conditions and stipulations.

## A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.

(1) The cost of compensatory afforestation on the CA land (6.5 ha) at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate

provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.

- (2) The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 3.142 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and letter No.5-3/2011-FC(Vol-I) dated 6/1/2022 in this regard.
- (3) All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).
- (4) The KML files of the area to be diverted and the CA area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details and submitting compliance report for seeking Stage-II approval.
- (5) The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
- (6) Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.
- (7) The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).

B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:

- (1) Legal status of the forest land shall remain unchanged.
- (2) Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 6.5 ha. degraded forest land (Site –Bhaikh, Range Jahanabad, Compartment No.38 under Gaya Forest Division) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species should be avoided.

- (3) Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
- (4) User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision and permission of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department. Further, in view of the State Government's recommendation, such number of trees whose removal is unavoidable, and whose translocation (species, number and girth to be decided by SFD) is practicable, will be translocated to the extent possible at the cost of user agency.
- (5) The State Forest Department should raise Strip Plantation on both sides of the road as per the IRC norms.
- (6) (a) The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged in construction activities do not damage the nearby forest flora and fauna.
  - (b) The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.
- (7) The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.
- (8) (a) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
  - (b) The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life/ requirement.
  - (c) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.
- (9) Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.

After receipt of the report from the State Government regarding due compliance and fulfillment of the above conditions and stipulations, formal approval will be issued in this regard under Section 2 of Forest (Conservation) Act, 1980. Transfer of forest land by the State Government to the user agency should not be given effect to till formal order approving diversion of forest land is issued by the

Ministry of Environment, Forest and Climate Change. To facilitate speedy execution of this project, the in-principle approval may be considered for issuance of working permission for commencement of works by the competent authority, if the required funds for NPV and all other compensatory levies specified in the in-principle approval are realized from the user agency and accordingly the State Government, by passing an order, may allow the commencement of work of the linear project in forest land for a period of one year (The detail guideline issued vide Ministry letter No. 11-306/2014-FC, dated 28.08.2015 may be referred).

विश्वासभाजन

(शशि शंकर)

सहायक वन महानिरीक्षक

### प्रतिलिपि:-

1. आई॰जी॰एफ॰, आर॰ओ॰एच॰क्यू॰, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003.

- 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff)/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक- सह नोडल पदाधिकारी (एफ. सी.), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खां मार्ग, पटना-800014.
- 3. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गया वन प्रमण्डल, गया, बिहार।
- 4. परियोजना निदेशक, NHAI, PIU, गया, बिहार 823001.
- 5. गार्ड फाईल।

सहायक वन महानिरीक्षक